पी एंड टी अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी वेलफ़ेयर संघ (पंजीकृत) और अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

29 अगस्त, 1988

[ई. एस. वेंकटरमैया, एस. नटराजन और एन. डी. ओझा, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 16, 330, 332, 334 और 335-पी एंड टी विभाग में पदोन्नति के पद-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षण-1983 की नई योजना में खोए हुए लाभ-अन्य विभागों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को लाभ मिलना जारी है-सरकार ने डाक और टेलीग्राफ विभाग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को समान लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया।

सिविल सेवा-पी एंड टी विभाग-पदोन्नति-एससी, एसटी कर्मचारियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण-नई योजना, 1983-एआईएल कर्मचारियों को बाद में पदोन्नति मिलेगी। 16 वर्ष-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को कम अवधि के भीतर पदोन्नति मिलने का लाभ-सरकार ने पी एंड टी विभाग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए आदेश जारी करने का निर्देश दिया, जैसा कि अन्य विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को मिलता है।

1968 में जारी अपने पहले के आदेश के स्थान पर, केंद्र सरकार ने 1972 में योग्यता के अधीन वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में अपनी नीति को अधिसूचित किया। जब भी इस तरह की पदोन्नति ग्रेड या सेवाओं में श्रेणी-I, श्रेणी-II,

श्रेणी-II और श्रेणी-V पदों पर नियुक्तियों में की जानी थी, जिसमें सीधी भर्ती का तत्व, यदि कोई हो, तो 50 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 71 प्रतिशत रिक्तियों को क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया जाना था।नियुक्ति अधिकारियों को तदनुसार पदोन्नति करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दूसरों की तुलना में बहुत पहले उच्च श्रेणी में पदोन्नति प्राप्त करने का लाभ मिल सके।

1974 में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 15 प्रतिशत/71/2 प्रतिशत रिक्तियों के आरक्षण का निर्देश देते हुए चयन श्रेणी के पदों पर पदोन्नति/नियुक्तियों द्वारा भरे गए पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संबंध में और निर्देश जारी किए गए थे।

डाक और तार विभाग में, उपरोक्त नीति 1983 तक जारी रही जब संचार मंत्रालय और डाक और तार कर्मचारियों के कुछ संघों के बीच एक समझौता हुआ और तब तक पी एंड टी विभाग में अपनाई जाने वाली पदोन्नति की नीति से संबंधित एक नया आदेश जारी किया गया था।इस नीति के तहत, समूह सी और समूह डी में बुनियादी ग्रेड से संबंधित सभी अधिकारी, जिनमें या तो बाहर से और/या निचले संवर्गों से सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती होती थी और जिन्होंने उस ग्रेड में 16 साल की सेवा पूरी कर ली थी, उन्हें अगले उच्च ग्रेड में रखा जाएगा। चाहे कोई कर्मचारी सामान्य श्रेणी का हो या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी का, उसे 16 साल की सेवा पूरी करने पर पदोन्नति मिलती थी। पिछली योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए 20 से 2 साल की अवधि के भीतर पदोन्नति प्राप्त करना संभव था, जबकि अन्य कर्मचारियों को लगभग 20 से 23 साल तक इंतजार करना पड़ा। इस प्रकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त तुलनात्मक लाभ को छीन लिया गया।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा कोई विशिष्ट आदेश जारी नहीं किया गया था, हालांकि नई योजना के खंड 6 में इसके लिए प्रावधान किया गया था। लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान करने वाले पहले के आदेशों को लागू नहीं किया गया था।एससी और एसटी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ से वंचित करने वाली नई नीति से व्यथित याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया।

याचिकाकर्ताओं ने नई योजना के खंड 6 के तहत एक आदेश जारी करने के लिए भारत सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया, जिसमें उन्हें ऐसा अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाए जैसा कि अन्य विभागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को मिलता है।

प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि नई योजना सभी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद थी क्योंकि उन सभी को 16 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्वचालित पदोन्नति मिलेगी। एक संवर्ग और यह कि यह पी एंड टी विभाग के कर्मचारियों के संघों की सहमति से किया गया था।

रिट याचिका की अनुमति देते हुए अभिनिर्धारित किया-

1. कम अवधि के भीतर पदोन्नति का लाभ अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मिल रहा है और अन्य विभागों में अनुसूचित जनजातियों को बांधा जा रहा है और केवल याचिकाकर्ता ही इससे वंचित रहे हैं।इस तरह का अभाव संविधान के समानता खंड का उल्लंघन करता है।हालांकि यह सच हो सकता है कि कोई भी रिट सामान्य रूप से सरकार को अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण देने के लिए मजबूर करने के लिए जारी नहीं की जा सकती है, जो कि एक सक्षम खंड है, जिन परिस्थितियों में डाक और

तार विभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से वंचित हैं, ऐसे आरक्षण का लाभ जो वे पहले प्राप्त कर रहे थे, जबकि अन्य जो अन्य विभागों में समान रूप से स्थित हैं, उन्हें इसका आनंद लेने की अनुमति है, सरकार की कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बनाते हैं और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप आमंत्रित करते हैं। [629 जी-एच; 630 ए-बी]

2. जिन तरीकों से सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को इस तरह के मामलों में कुछ अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकती है, जहां उच्च संवर्ग में पदोन्नति एक समयबद्ध है, उनमें से एक यह निर्देश देना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को दूसरों के लिए निर्धारित सेवा की अवधि से कम अवधि पूरी करने पर उच्च संवर्ग में पदोन्नत किया जा सकता है।इस विशेष मामले में सरकार को यह निर्देश देने का अधिकार है कि 16 साल की सेवा पूरी होने पर अन्य सभी उच्च संवर्ग में पदोन्नत होने के हकदार होंगे, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 2 या 13 साल की सेवा पूरी होने पर उच्च संवर्ग में पदोन्नत किया जा सकता है। समान परिणाम प्राप्त करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। यह किस तरह से होना चाहिए, यह सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है। यह सरकार द्वारा तय किया गया कि मामले के सभी पहलुओं पर विचार करें। [630 बी-एफ]

3. भारत सरकार चार महीने के भीतर दिनांक 23.11.1983 पत्र के खंड 6 के तहत एक आदेश जारी करेगी, जिसमें डाक और तार विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा, जो अन्य विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले समान लाभों के अनुरूप है। सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला कोई भी आदेश संभावित रूप से काम करेगा। तथापि, वे सभी पदोन्नति जो अब तक दिनांक

23.12.1983 में निहित नीति के अनुसरण में की गई हैं और जो इसके बाद उस तारीख तक की जा सकती हैं जब तक कि खंड 6 के तहत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला निर्देश लागू नहीं हो जाता है, वे निर्बाध रूप से लागू होंगी।[630 एफ-एच; 631 ए]

मुल न्यायनिर्णयः रिट याचिका (सिविल) संख्या 1003-1005/1984

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)।

याचिकाकर्ताओं के लिए आर. के. गर्ग, पंकज कालरा और पी. के. जैन।

प्रतिवादियों के लिए वी. सी. महाजन, सुश्री ए. सुभाशिनी, सी. वी. सुब्बा राव, गिरीश चंद्र के. मेहता, ध्रुव मेहता, अमन वचेर, एस. एम. सरीन और जगन्नाथ गौले (एन. पी.)।

न्यायालय के निर्णय वेंकटरमैया, जे. द्वारा दिया गया।

भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों से संबंधित लोग भारतीय संविधान के उत्साहपूर्वक संरक्षित बच्चे हैं। संविधान के अनुच्छेद 46 में प्रावधान है कि राज्य विशेष ध्यान के साथ शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। लोगों के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाना। जबकि संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (1) में यह प्रावधान है कि राज्य केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा, उस अनुच्छेद के खंड (4) में प्रावधान है कि उक्त अनुच्छेद या संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड (2) में कुछ भी राज्य को इसके लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा। नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूची जातियों और अनुसूची जनजातियों के लिए

उन्नति। इसी तरह, जबकि संविधान के अनुच्छेद 16 के खंड (1) में प्रावधान किया गया है कि राज्य के तहत किसी भी पद पर नियुक्ति या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी और उक्त अनुच्छेद के खंड (2) में प्रावधान किया गया है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या उनमें से किसी के आधार पर राज्य के तहत किसी भी रोजगार या पद के संबंध में अयोग्य या भेदभाव नहीं करेगा, उक्त अनुच्छेद के खंड (4) में प्रावधान है कि उस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, जिसका राज्य की राय में राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 में लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 334 में दी गई अवधि तक सभा और राज्यों की विधानसभाओं में संविधान का अनुच्छेद 335, जो इस मामले के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक है, यह प्रावधान करता है कि संघ या किसी राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों को प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ-साथ ध्यान में रखा जाएगा।

हालाँकि, वर्तमान मामला वह है जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति के स्तर पर रिक्तियों के आरक्षण के माध्यम से दी गई रियायत को गुप्त तरीके से वापस ले लिया गया है। इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता 1 और 2 पी एंड टी अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण संगठन (विनियमित) हैं। दिल्ली और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी पी एंड टी विभाग, नई दिल्ली और याचिकाकर्ता 3 डाक और टेलीग्राफ विभाग में एक कर्मचारी हैं। पत्र सं. 27/2/71-एस्ट (एस. सी. टी.) द्वारा

दिनांक 27.11.1972 कार्मिक विभाग द्वारा जारी किया गया, सरकार ने योग्यता के अधीन वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति/पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में अपनी नीति के बारे में सूचित किया। 11. 7. 1968 के पूर्ववर्ती सरकारी आदेश में निहित आदेशों के अधिक्रमण में सरकार द्वारा अपनाया गया। उक्त नीति के तहत अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत रिक्तियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7-1/2 प्रतिशत का आरक्षण किया गया था, जहां भी योग्यता के अधीन वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जानी थी, सभी वर्ग I, वर्ग II, वर्ग III और वर्ग V [ग्रेड या सेवाओं में नियुक्तियों में जिनमें प्रत्यक्ष भर्ती का तत्व, यदि कोई हो, 50 प्रतिशत से अधिक नहीं था।उपरोक्त आरक्षण को लागू करने के लिए सरकार ने नियुक्ति अधिकारियों को एक वर्ष में आरक्षित रिक्तियों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक अलग 40-बिंदु रोस्टर बनाए रखने का निर्देश दिया, जिसमें बिंदु 1, 8, 14, 22, 28 & 36 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया जाना था और अंक 4,17 और 31 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने थे। नियुक्ति अधिकारियों को उसमें निहित निर्देशों के अनुसार पदोन्नति करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उच्च पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का लाभ मिल सके। कैडर उन कर्मचारियों की तुलना में बहुत पहले का था जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं थे। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के ओ. एम. सं. 8/11/73-ए. एस. टी. वाले पत्र द्वारा।(एस. सी. टी.) दिनांक 12.9.1974 सभी मंत्रालयों को संबोधित करते हुए चयन श्रेणी के पदों पर पदोन्नति/नियुक्तियों द्वारा भरे गए पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में आगे के निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत रिक्तियों के आरक्षण का निर्देश दिया गया

था।पी एंड टी बोर्ड के तहत काम करने वाले डाक और तार कर्मचारियों के संबंध में, संचार मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 31-19/74-पीई-I दिनांक 15.6.1974 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कुछ अन्य लाभ प्रदान करते हुए पदोन्नति द्वारा पदों को भरने के संबंध में कुछ और निर्देश दिए।उपरोक्त तीन सरकारी पत्रों में निहित आरक्षण की नीति डाक और तार विभाग में वर्ष 1983 तक जारी रही।ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 1983 में संचार मंत्रालय और डाक और तार विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के कुछ संघों के बीच एक समझौता हुआ था और उक्त समझौते के परिणामस्वरूप डाक और तार विभाग में अपनाई जाने वाली पदोन्नति की नीति से संबंधित एक नया आदेश आरक्षण की योजना के स्थान पर जारी किया गया था, जिसका तब तक पालन किया जा रहा था। उक्त नई नीति, जिसकी वैधता को हमारे सामने चुनौती दी गई है, वह सभी मंडलियों के प्रमुखों को संबोधित पत्र संख्या 31-26/83-पीई-I दिनांक 17.12.1983 में निहित है। इस नई नीति के तहत यह निर्णय लिया गया कि समूह सी और समूह डी में बुनियादी ग्रेड से संबंधित सभी अधिकारियों को, जिनके लिए या तो बाहर से और/या निचले संवर्गों से सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती की जाती थी, और जिन्होंने उस ग्रेड में 16 साल की सेवा पूरी कर ली थी, उन्हें अगले उच्च ग्रेड में रखा जाएगा। यह आरोप लगाया जाता है कि इस नीति को उच्च श्रेणी में पदोन्नत किए बिना लगभग 20 से 23 वर्षों तक एक विशेष श्रेणी में आदेशमचारियों के ठहराव के प्रभावों को दूर करने के लिए पेश किया गया था।ऐसा प्रतीत होता है कि उस योजना के तहत जो 30.11.1983 से पहले प्रचलित थी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए 10 से 12 साल की अवधि के भीतर उच्च संवर्ग में पदोन्नति प्राप्त करना संभव था, जबकि अन्य कर्मचारियों को लगभग 20 से 23 साल तक इंतजार करना पड़ा। इस प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को एक लाभ प्रदान किया गया था

क्योंकि वे कम अवधि के भीतर पदोन्नति प्राप्त कर सकते थे। नई नीति के तहत इस तथ्य के बावजूद कि कोई कर्मचारी सामान्य श्रेणी से संबंधित है या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से संबंधित है, वह 16 साल पूरे होने पर उच्च संवर्ग में पदोन्नति प्राप्त करने में समर्थ होगा। इस प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को तुलनात्मक लाभ मिल रहा था। सभी कर्मचारियों, अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को हटा दिया गया और उन्हें बराबर रखा गया। हालाँकि, 17.12.1983 दिनांकित उक्त पत्र का खंड 6, जिसमें नई नीति शामिल है, इस प्रकार हैः

“6. समयबद्ध एक पदोन्नति योजना के तहत पदोन्नति के लिए एससी/एसटी समुदायों के लिए आरक्षण से संबंधित सामान्य आदेश तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि इस संबंध में कोई विशिष्ट आदेश बाद में जारी नहीं किया जाता है।”

यह स्वीकार किया जाता है कि सरकार द्वारा अब तक खंड 6 के अनुसार कोई विशिष्ट आदेश जारी नहीं किया गया है।लेकिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण प्रदान करने वाले पहले के आदेशों को लागू नहीं किया गया था। सरकार द्वारा दिनांकित 23.12.1983 में निहित नीति को लागू करने में की गई कार्रवाई से व्यथित याचिकाकर्ताओं ने यह याचिका दायर की है, जिसमें उक्त कार्रवाई पर सवाल उठाया गया है। प्रतिवादी द्वारा याचिका का विरोध किया जाता है। सरकार की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि 'समयबद्ध एक पदोन्नति योजना' दिनांकित 23.12.83 पत्र में निहित हो। यह सभी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद था क्योंकि वे सभी एक संवर्ग में 16 साल की सेवा पूरी करने पर स्वचालित रूप से उच्च संवर्ग में पदोन्नत हो जाएंगे और यह डाक और तार विभाग के कर्मचारी संघों की सहमति से जारी किया गया था।

इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि केंद्र सरकार के कई अन्य विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण की योजना निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी में पदोन्नति के मामलों में प्रचलित है, जब वे योग्यता के अधीन वरिष्ठता के आधार पर की जाती हैं और उक्त नीति के तहत अन्य विभागों में काम करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को एक अतिरिक्त लाभ दिया गया है जो अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध नहीं था और डाक और तार विभाग में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को इसी तरह का लाभ मिल रहा था। यहां तक कि अन्य विभागों में लागू डाक और तार विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित सामान्य आदेशों को शून्य करने वाले 23.12.1983 के पत्र में भी सरकार द्वारा विशिष्ट आदेश जारी करने का प्रावधान है, जिसके तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य कुछ अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं।मान लीजिए कि आज तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि सरकार को उन्हें इस तरह का अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए विशिष्ट आदेश जारी करने का निर्देश जारी किया जाना चाहिए। हम महसूस करते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया दावा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से उचित है कि अन्य विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को भी इसी तरह का लाभ मिल रहा है और केवल वे ही इससे वंचित हैं। इस तरह का अभाव संविधान के समानता खंड का उल्लंघन करता है।हालांकि यह सच हो सकता है कि अनुच्छेद 16 (4) के तहत आरक्षण देने के लिए सरकार को मजबूर करने वाला कोई भी रिट जारी नहीं किया जा सकता है, जो केवल एक सक्षम खंड है, डाक और तार विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे आरक्षण के लाभ से वंचित हैं जो वे पहले प्राप्त कर रहे

थे, जबकि अन्य जो अन्य विभागों में समान रूप से स्थित हैं, उन्हें इसका लाभ उठाने की अनुमति है, सरकार की कार्रवाई को भेदभावपूर्ण बनाते हैं और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप आमंत्रित करते हैं।

जिन तरीकों से सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को इस तरह के मामलों में कुछ अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकती है, जहां उच्च संवर्ग में पदोन्नति समयबद्ध है, उनमें से एक यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को निर्देश दिया जाए कि दूसरों के लिए निर्धारित सेवा अवधि की तुलना में कम सेवा अवधि पूरी करने पर उच्च संवर्ग में पदोन्नत किया जाता है। इस विशेष मामले में सरकार यह निर्देश दे सकती है कि 16 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अन्य सभी उच्च संवर्ग में पदोन्नत होने के हकदार होंगे, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 12 या 13 वर्ष की सेवा पूरी होने पर उच्च संवर्ग में पदोन्नत किया जा सकता है। समान परिणाम प्राप्त करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। डाक और तार विभाग में काम करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त लाभ प्रदान करने का दावा, जो उस अतिरिक्त लाभ के अनुरूप हो सकता है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य भारत सरकार के अन्य विभागों में सेवा में दक्षता के रखरखाव को नुकसान पहुंचाए बिना प्राप्त कर रहे हैं, एक उचित दावा प्रतीत होता है। यह किस तरह से किया जाना चाहिए, यह सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है। मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह सरकार को तय करना चाहिए।

इसलिए हम भारत सरकार को डाक और तार विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए दिनांकित पत्र के खंड 6 के तहत एक आदेश जारी करने का निर्देश जारी करते हैं, जो भारत सरकार के अन्य विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के

कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किए जा रहे समान लाभों के अनुरूप है।सरकार आज से चार महीने के भीतर इस तरह का आदेश जारी करेगी।सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला कोई भी आदेश संभावित रूप से काम करेगा।दिनांकित 23.12.1983 पत्र में निहित नीति के अनुसरण में अब तक जो भी पदोन्नति की गई है और जो इसके बाद उस तारीख तक की जा सकती है जब तक कि खंड 6 के तहत सरकार द्वारा ए को निर्देश जारी नहीं किया जाता है, वह जारी नहीं किया जाएगा।

तदनुसार इस याचिका की अनुमति दी जाती है। कोई लागत नहीं।

जी.एन. याचिका की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।